



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 322]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 5, 2016/आश्विन 13, 1938

No. 322]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016/ASVINA 13, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2016

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

विषय : चीन जन. गण., जापान और कारिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट-(टीडीआई) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत

संख्या 14/36/2016-डीजीएडी: मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड (जिसे आगे याचिकाकर्ता या आवेदक कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., जापान और कोरिया (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट-टीडीआई (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

2. यह आवेदन घरेलू उद्योग के रूप में मै. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

3. आवेदक कंपनी ने दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तु के एक पात्र उत्पादक हैं। इस प्रकार, रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक का उत्पादन घरेलू उत्पादन का समान वस्तु के सकल घरेलू उत्पादन में 'प्रमुख हिस्सा' बनता है; वास्तव में घरेलू उत्पादन में उनका 100 प्रतिशत हिस्सा है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन. गण., जापान और कोरिया के मूल का अथवा वहां से निर्यातित टोलीन डि-आइसोसायनेट-टीडीआई है।

5. टोलीन डि-आइसोसायनेट (टीडीआई) एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$ है। छह संभव आइसोमर्स में से दो वाणिज्यिक रूप में महत्वपूर्ण हैं : 2,4-टीडीआई (सीएस: 584-84-9) और 2,6-टीडीआई (91-08-7)। 2, 4-टीडीआई को शुद्ध रूप में उत्पादित किया जाता है, परंतु टीडीआई को प्रायः 2,4 और 2,6 आइसोमर्स के क्रमशः 80/20 और 65/35 मिश्रणों में बेचा जाता है। वर्तमान जाँच में पीयूसी उस टीडीआई से संबंधित है जिसकी आइसोमर मात्रा का अनुपात (80:20) है और कोई अन्य ग्रेड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

6. टीडीआई एक स्वच्छ तरल होता है और उसका प्रयोग फ्लेक्सिबल पालीयूरेथेन फोम, फर्नीचर कुशन, औद्योगिक गैस्केट, खेल और चिकित्सा प्रयोग के लिए सुरक्षा पैडों, आटोमोबाइल : सीटों, फर्नीचर, लाइनिंग, सन वाइजर आदि, मैकिंग: इलेक्ट्रानिक मदों, शीतित खाद्यों, दवाइयों, आडियो-वीडियो कंप्यूटर सीडी आदि में होता है।

7. चूंकि टीडीआई एक कार्बनिक रसायन है इसलिए इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत और आगे उपशीर्ष 29291020 के अधीन वर्गीकृत किया जाता है, जो टोलीन डि-आइसोसायनेट से संबंधित है। तथापि जैसा आवेदक ने बताया है इस शीर्ष में आइसोमर (80:20) से इतर कतिपय ग्रेड भी शामिल हैं और इसलिए वर्गीकरण केवल सांकेतिक है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के आयात कुछ अन्य उपशीर्षों जैसे 29094300, 29291090, 29291010, 38249090 और 39095000 के अधीन भी किए जाने की सूचना मिली है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्तावित जाँच के दायरे पर और अनुशंसित किए जाने वाले किसी उपाय पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदकों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

9. आवेदक ने यह दावा भी किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी प्रस्तावित वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

10. वर्तमान जांच चीन जन. गण., जापान और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और उसके मामले में नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत को विधिवत रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ के लिए आवश्यक समायोजनों के साथ नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार लगाया गया है।

इसके अलावा आवेदक ने इस कारण से जापान और कोरिया गणराज्य के संबंध में भी सामान्य मूल्य का परिकलन किया है कि वे उक्त देशों में संबद्ध वस्तु की घरेलू कीमतों के संबंध में न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य और न ही विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने में सक्षम रहे थे। इसके अलावा ऐसी सूचना सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी ने इन देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर इस जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्य के आधार पर भी विचार किया है। याचिकाकर्ता ने कच्ची सामग्री की कीमत, खपत कारक, घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागत और लाभ के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

निर्यात कीमत

12. आवेदक ने आईबीआईएस से प्राप्त आयात आकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत को निर्धारित किया है चूंकि डीजीसीआईएंडएस के सारांश आकड़े पीयूसी के लिए विश्वसनीय नहीं हैं। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, अंतरदेशीय भाड़े, डी/ओ प्रभार, प्रहस्तन और निकासी प्रभार के लिए कीमत संबंधी समायोजनों का दावा किया गया है।

पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देशों के संबंध में भारी पाटन मार्जिन दर्शाता है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो समग्र रूप से और उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री, भारी वित्तीय घाटा, नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय, विभिन्न मापदंडों पर नकारात्मक वृद्धि आदि से परिलक्षित होता है। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई 'वास्तविक क्षति' के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

15. पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि नियमावली के नियम 5 के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, ताकि

कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

पाटनरोधी जाँच की शुरुआत

16. पूर्वोक्त पैराग्राफों के मद्देनजर निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करते हैं।

जांच अवधि (पीओआई)

17. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 (12 महीने) तक की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2012-13, 2013-14, 2014-15 और जाँच अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

18. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देशों की सरकार, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग**

**जीवन तारा बिल्डिंग, चौथा तल, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001**

19. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

20. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

23. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी

हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

24. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध/रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

28. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

29. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping And Allied Duties)

New Delhi, the 5th October, 2016

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Initiation of Anti-dumping investigation concerning imports of 'Toluene Di-Isocyanate- (TDI)' originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.

No.14/36/2016-DGAD:— M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited (hereinafter referred to as “petitioner” or “the applicant”) have filed an application before the Designated Authority(hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act,1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty concerning imports of Toluene Di- Iso cyanate- TDI (hereinafter also referred to as the subject goods or product under consideration), originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP (hereinafter also referred to as the subject countries).

Domestic Industry & Standing

2.The Application has been filed by M/s Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Limited as the domestic industry.

3. The applicant company has claimed that they are the sole producer of subject good in India. Thus, as per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes “a major proportion” of the domestic production; in fact 100% share of domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti- Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the anti- dumping Rules.

Product under consideration

4. The product under consideration (PUC) in the present investigation is Toluene Di- Isocyanate- TDI originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP.

5. Toluene di-isocyanate (TDI) is an organic compound with the formula $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_3(\text{NCO})_2$. Two of the six possible isomers are commercially important: 2,4-TDI (CAS: 584-84-9) and 2,6-TDI (CAS: 91-08-7). 2,4-TDI is produced in the pure state, but TDI is often marketed as 80/20 and 65/35 mixtures of the 2,4 and 2,6 isomers respectively. The PUC in the present investigation concerns TDI having isomer content in the ratio of (80:20) and any other grades are beyond the scope of product under consideration.

6. TDI is a clear liquid and is used for production of Flexible Polyurethane Foam, Furniture cushion, Industrial Gaskets, Protective pads for Sports & Medical use, Automobiles: Seats, Furniture, Lining, Sun visors etc, Packing: Electronic items, Frozen Foods, Medicines, Audio-video Computer CD's etc.

7. TDI being an organic chemical is categorised under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under subheading 29291020 which pertains to Toluene di-isocyanate. However, as submitted by the applicant, this heading includes certain grades other than isomers (80:20) hence the classification is indicative only. It has also been claimed by the applicant that the imports of the subject goods have been reported under some other subheadings also such as 29094300, 29291090, 29291010, 38249090 and 39095000. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the proposed investigation and any measures to be recommended to be imposed.

Like Article

8. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable.

9. The applicant has further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the product under consideration being imported from the subject countries.

Countries involved

10. The present investigation is in respect of dumping of the product under consideration from China PR, Japan and Korea RP.

Normal Value

11. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy country and its normal value be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules with due adjustments for selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

Further, the applicant has also constructed the normal values in respect of Japan and Korea RP on the grounds that they were neither able to get any documentary evidence nor reliable information with regard to domestic prices of the subject goods in the said countries. Further, such information is also not available in public domain. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in these countries also on the basis of constructed values as made available by the applicant for the purpose of this initiation. The petitioner has claimed normal value on the basis of raw material price, consumption factor, conversion cost of domestic industry and profit.

Export Price

12. The applicant has determined the export price on the basis of import data procured from IBIS since the DGCI&S summary data is not reliable for the PUC. Price adjustments have been claimed on account of Ocean freight, Marine insurance, inland freight, D/O Charges, Handling & clearing charges.

Dumping Margin

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margin in respect of all the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price suppression, price underselling, significant financial losses, negative ROCE, negative growth in various parameters etc. There is sufficient prima facie evidence of the 'material injury' suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

15. From the foregoing, the Authority prima facie finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Para 5 of the Rules, to

determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Initiation of anti-dumping investigation

16. The Designated Authority, in view of the foregoing paragraphs, initiates antidumping investigations into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Period of Investigation (POI)

17. The period of investigation for the purpose of present investigation is from 1st April 2015 to 31st March 2016 (12 months). The injury investigation period will however, cover the periods 2012-13, 2013-14, 2014-15 and the POI.

Submission of information

18. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Department of Commerce,
Jeevan Tara Building, 4th Floor
5, Parliament Street
New Delhi -110001

19. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

20. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

22. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

23. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non-confidential version must be submitted by all the interested parties.

24. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

28. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

29. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A.K, BHALLA Addl. Secy. & Designated Authority